PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Fri, 02 Jun 2017, Page 18
Width: 21.96 cms, Height: 21.05 cms, a3r, Ref: 37.2017-06-02.189

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल की : जेटली

1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, रणनीतिक साझेदारी से आएगा रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मोदी सरकार बीते तीन साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने में कामयाब रही है। साथ ही सरकार ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) सहित कई लंबित सुधारों को लागू किया है। वहीं, जैम (जन-धन, आधार और मोबाइल) के जरिए सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार व लीकेज को खत्म करने में अहम भूमिका निभायी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने मंत्रालय की तीन वर्ष की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कार्यकाल में अनिर्णय की स्थिति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते भारतीय अर्थव्यस्था की विश्वसनीयता में कमी आई थी। मोदी सरकार ने बीते तीन साल में लंबित सुधारों को लागू करके और बाजार तंत्र आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को बहाल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने शासन प्रक्रिया में सुधार करते हुए सरकारी निर्णयों में मनमानी की परंपरा को खत्म किया है।

जीएसटी को ऐतिहासिक कर सुधार करार देते हुए जेटली ने कहा कि मौजूदा सरकार ने जीएसटी काउंसिल के रूप में एक संघीय संस्था बनाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही है। इसलिए उद्योग जगत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जेटली ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वह जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रस्तावित जीएसटी की दरों में कटौती की मांग करने से पहले संबंधित वस्तु व सेवाओं पर टैक्स की मौजूदा दरों को देखें। नोटबंदी के साल में देश के विकास में गिरावट आने के सवाल पर जेटली ने कहा कि मौजूदा वैश्विक माहौल में भारत सात से आठ प्रतिशत विकास दर हासिल कर रहा है जो ठीक-ठाक है। जेटली ने यह भी कहा कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में विकास दर में गिरावट के लिए अकेले नोटबंदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही में गिरावट घरेलू और वैश्विक कारकों के चलते आई है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से किए गए एफडीआइ नीति में सुधारों का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक हिस्सेदारी से एफडीआइ आएगा। बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा कि इस संबंध में कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ और कदम उठाए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए हाल में सरकार ने एक अध्यादेश भी जारी किया है। उन्होंने बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या को बड़ी चुनौती करार दिया। पशुओं की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जेटली ने कहा कि पशु हाट किसानों के लिए हैं न कि व्यापारियों के लिए। सरकार की अधिसूचना का यही प्रभाव है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून विद्यमान हैं और पशुओं के वध के संबंध में राज्यों के कानूनों पर सरकार की अधिसूचना का कोई असर नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली में बृहस्पतिवार को प्रेस कान्फ्रेंस में देश की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों को लेकर सवालों का जवाब देते केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। साथ में हैं वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार और अर्जुन राम मेघवाल ● प्रेट्र